संख्या : 796/आठ–1–23–08 बैठक/2017

प्रेषक,

अरूणेश कुमार द्विवेदी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त,**
   उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
   लखनऊ।
2. **उपाध्यक्ष,**
   समस्त विकास प्राधिकरण,
   उ0प्र0।
3. **अध्यक्ष/जिलाधिकारी,**
   समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
   उ0प्र0।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 **लखनऊ : दिनांक : 01-09-2023 ~~, अगस्त~~, 2023**

विषयः वित्तीय वर्ष–2023–24 में प्रदेश के मार्गो के अनुरक्षण/नवीनीकरण/गड्ढामुक्ति के संबंध में।

महोदय,

कृपया संयुक्त सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–6 के पत्र सं0–748/81–6–2023 दिनांक 09.08.2023 (छायाप्रति मय संलग्नक) का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि मा0 राष्ट्रीय मानवाधिकार, नई दिल्ली में विचाराधीन वाद सं0–2886/90/2/2022 दिनांक 04.07.2023 को हुई सुनवाई के पश्चात निर्गत आदेश दिनांक 28.07.2023 के प्रस्तर–23 से 27 पर उ0प्र0 सरकार से सम्बन्धित अतिरिक्त/पूर्ण रिपोर्ट दिनांक 31.08.2023 तक मा0 आयोग को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं एवं यह भी अवगत कराया गया है कि प्रस्तर–27 के बिंदु–एफ में मार्गो के गड्ढामुक्ति के सम्बन्ध में अद्यतन स्थिति से अवगत कराये जाने हेतु अपेक्षा की गयी है।

2. उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत प्रकरण में प्रदेश के मार्गो के अनुरक्षण/नवीनीकरण/गड्ढामुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में एक कार्ययोजना तैयार कर मार्गो के गड्ढामुक्ति के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्देश दिये गये हैं:–

(1) सभी मार्गों को यथाशीघ्र गड्ढामुक्त (Pothole Free) कर दिया जाये।
(2) इस आशय का प्रमाण–पत्र दिया जाये कि लक्षित मार्गों के अतिरिक्त कोई सड़क गड्ढामुक्त किये जाने के लिये अवशेष नहीं है।
(3) लक्ष्य को निर्धारित करते समय चेक कर लिया जाये कि निर्धारित लक्ष्य बिल्कुल सही है तथा इसमें किसी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है।

3– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया दिये गये निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित कराते हुए विस्तृत कार्ययोजना तैयार करते हुए वांछित

सूचना निर्धारित प्रारूप पर निदेशक, आवास बन्धु को दिनांक 01.09.2023 तक उपलब्ध कराते हुए उसकी एक प्रति शासन को भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः–यथोक्त।

भवदीय,

1.9.2023

(अरूणेश कुमार द्विवेदी)
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।

2– निदेशक, आवास बन्धु को इस आशय से प्रेषित कि सभी सम्बन्धितों से कृत कार्यवाही की अनुपालन आख्या प्राप्त कर समेकित सूचना शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,

(किशलय सिंह)
अनु सचिव।

संख्या :796 /आठ–1–23–08 बैठक/2017

प्रेषक,

अरूणेश कुमार द्विवेदी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त,**
   उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
   लखनऊ।
2. **उपाध्यक्ष,**
   समस्त विकास प्राधिकरण,
   उ0प्र0।
3. **अध्यक्ष/जिलाधिकारी,**
   समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
   उ0प्र0।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 **लखनऊ : दिनांक : 01-09-2023 ~~अगस्त~~, 2023**

विषयः वित्तीय वर्ष–2023–24 में प्रदेश के मार्गो के अनुरक्षण/नवीनीकरण/गड्ढामुक्ति के संबंध में।

महोदय,

कृपया संयुक्त सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–6 के पत्र सं0–748/81–6–2023 दिनांक 09.08.2023 (छायाप्रति मय संलग्नक) का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि मा0 राष्ट्रीय मानवाधिकार, नई दिल्ली में विचाराधीन वाद सं0–2886/90/2/2022 दिनांक 04.07.2023 को हुई सुनवाई के पश्चात निर्गत आदेश दिनांक 28.07.2023 के प्रस्तर–23 से 27 पर उ0प्र0 सरकार से सम्बन्धित अतिरिक्त/पूर्ण रिपोर्ट दिनांक 31.08.2023 तक मा0 आयोग को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं एवं यह भी अवगत कराया गया है कि प्रस्तर–27 के बिंदु–एफ में मार्गो के गड्ढामुक्ति के सम्बन्ध में अद्यतन स्थिति से अवगत कराये जाने हेतु अपेक्षा की गयी है।

2. उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत प्रकरण में प्रदेश के मार्गो के अनुरक्षण/नवीनीकरण/गड्ढामुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में एक कार्ययोजना तैयार कर मार्गो के गड्ढामुक्ति के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्देश दिये गये हैं:–

(1) सभी मार्गों को यथाशीघ्र गड्ढामुक्त (Pothole Free) कर दिया जाये।
(2) इस आशय का प्रमाण–पत्र दिया जाये कि लक्षित मार्गों के अतिरिक्त कोई सड़क गड्ढामुक्त किये जाने के लिये अवशेष नहीं है।
(3) लक्ष्य को निर्धारित करते समय चेक कर लिया जाये कि निर्धारित लक्ष्य बिल्कुल सही है तथा इसमें किसी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है।

3– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया दिये गये निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित कराते हुए विस्तृत कार्ययोजना तैयार करते हुए वांछित

सूचना निर्धारित प्रारूप पर निदेशक, आवास बन्धु को दिनांक 01.09.2023 तक उपलब्ध कराते हुए उसकी एक प्रति शासन को भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः—यथोक्त।

भवदीय,

(अरूणेश कुमार द्विवेदी)
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपिः—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।

2— निदेशक, आवास बन्धु को इस आशय से प्रेषित कि सभी सम्बन्धितों से कृत कार्यवाही की अनुपालन आख्या प्राप्त कर समेकित सूचना शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,

(किशलय सिंह)
अनु सचिव।

File No 81-6099/113/2022-06-

वीडियो कान्फ्रेंसिंग, दिनांक 04.09.2023, मध्यान्ह 11:30 बजे
संख्या–748 / 81–6–2023

प्रेषक,

रवि शंकर मिश्र

सेवा में

1 अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–6 लखनऊ दिनांक अगस्त, 2023

विषय–

महोदय

दिनांक 31.03.2023 वाद संख्या–2886 / 90 / 0 / 2022 में दिनांक 04.09.2023 को मध्यान्ह 11:30 बजे हाइब्रिड मोड के माध्यम से आहूत बैठक में सुसंगत सूचनाओं सहित प्रतिभाग करना सुनिश्चित करें।

माo आयोग के समक्ष हाइब्रिड मोड के माध्यम से सुनवाई हेतु दिनांक 04.09.2023 मध्यान्ह 11:30 बजे से आयोजित बैठक में सुसगत सूचनाओं सहित प्रतिभाग करने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोक्त।

Signed by रवि शंकर मिश्र
Date: 09-08-2023 13:38:14
Reason Approved

भवदीय,

(रवि शंकर मिश्र)

संख्या एवं दिनांक तदैव

97

/6/2023/, -6

Gmail

Ashish Tiwari, Secretary, EF&CC Dept, GoUP <sachivforest@gmail.com>

Fwd: Additional Information Called for(AIC) - 2886/90/0/2022

2 messages

PS forest <psforest2015@gmail.com> Mon, Jul 31, 2023 at 2:20 PM
To: sachiv forest <sachivforest@gmail.com>

संख्या 748/81-6-2023

---------- Forwarded message ----------
From: Rahat Ayukt, Uttar Pradesh <rahat@nic.in>
Date: Mon, Jul 31, 2023 at 2:03 PM
Subject: Fwd: Additional Information Called for(AIC) - 2886/90/0/2022
To: psforest2015 <psforest2015@gmail.com>

4100/SF/23
VS(GM)

Respected,
Sir/Madam

Please see the attached file.

From,

Relief Commissioner Office,
Govt. of Uttar Pradesh,
IInd Floor, Lal Bahadur Shastri Bhawan,
UP Secretariat, Lucknow, UP.
Contact- 0522-2238200, 2237515, 2215076

(आशीष तिवारी)
सचिव,
पर्यावरण, वन एवं
जलवायु परिवर्तन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

2214/VSGM/23

US(DC)/SO-6

31/07/2023

(घनश्याम मिश्र)
विशेष सचिव
पर्यावरण, वन एवं जलवायु
परिवर्तन विभाग
उ० प्र० शासन

From: "nhrc india" <nhrc.india2@nic.in>
To: cs-uttarpradesh@nic.in, csup@nic.in
Sent: Friday, July 28, 2023 7:10:17 PM
Subject: Additional Information Called for(AIC) - 2886/90/0/2022

Case No.- 2886/90/0/2022

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

(LAW DIVISION)

* * *

MANAV ADHIKAR BHAWAN, BLOCK-C,
G.P.O. COMPLEX, INA, NEW DELHI- 110023
Fax No.. 011-24651332 Website: www.nhrc.nic.in

Date : 28/07/2023

To,
THE CHIEF SECRETARY
GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH, 1ST FLOOR, ROOM NO. 110, LALBAHADUR SASTRI BHAWAN,
UTTAR PRADESH SECRETARIAT, LUCKNOW-226001
UTTAR PRADESH UTTAR PRADESH
Email- cs-uttarpradesh@nic.in,csup@nic.in

Sub : Complaint/Intimation from

HINDUSTAN TIMES
NEW DELHI
NEW DELHI , DELHI
0

SO-6 31/7/23

श्री दिवाकर 31/7/23

Subject: Additional Information Called for(AIC) - 2886/90/0/2022.

farmers till 31.03.2023; out of this, 7,719 machines have been provided to individual farmers in NCR. The PUSA decomposer is also successful in the State. Decomposing takes 25-30 days, and two crops take 45 days. The state has mandated the compulsory use of super SMS or other Crop Residue Management and frequently monitors at the Chief Secretary level. The state has planned large-scale IEC activities in which farmer awareness camps are also being organized. The state has introduced Bio Energy Policy-2022 to promote and provide subsidies on Agriculture waste-based Bio C.N.G./Bio Coal/ Bio Bricuettes/C.B.G. and to facilitate farmers, aggregators, manufacturers and entrepreneurs. By March 2025, five Bio-CNG plants will be constructed in the state, two in Muzaffar Nagar, two in Meerut and one in Saharanpur and, after that, the total capacity will go to 18,943 TPD from the current 14,710 TPD. Construction works are also going on in different places of the state, and the government is doing proper monitoring as per the annual agreement of the solid waste. Regarding construction and demolition, waste management, the gap is 266 MLD. The government has six processing facilities in place and under construction, we have two more, one with a capacity of 976 TPD by March 2024, and the target will be achieved shortly.

25. Concerning the plantation of trees, the representative of the State submits that the State is committed to increasing the green cover in the State. The last figure for 2021 says that 90% of re-plantation is done in forest areas, 85% in urban areas, and 80% in rural areas, as per the Forest Survey of India report. In the State itself, there are nurseries with over 49 crores of saplings. Every year, the Forest Department and 26 other Departments go for massive tree plantations in rural, urban and forest areas. 443 CNG buses are operating to control vehicular pollution, and 100 new CNG buses are being procured. There is, as yet no plan to introduce electric buses in the State.

26. The Commission has considered the oral submissions made by the representatives of the State of Uttar Pradesh on various steps/measures taken by them to prevent stubble burning in the State and also as to the action taken on the Commission's Advisory dated 24.9.2021 on the human rights of the persons engaged in hazardous cleaning. The Commission, therefore, directs the Chief Secretary, Govt. of Uttar Pradesh, to submit a comprehensive report within four weeks on the items mentioned in para 7 above.

27. In addition, the Commission would like a further report on the following queries from the Chief Secretary, Govt. of Uttar Pradesh, within four weeks.

a. The last social welfare meeting was held in 2019. The reasons for not having such meetings after that. Date for next meeting be submitted.

b. What time frame the state will meet the gap of TPD of solid waste.

c. Steps taken to promote sowing more basmati rice by the farmers.

d. Whether the state has reserved CRM machines for low-income farmers, who cannot afford it. If not done, adequate number be reserved and details of such machines reserved be submitted to the Commission.

e. Figures and details where plants and trees were planted and whether any third party is doing any survey about its survival. If so, reports thereof.

f. The latest figures where measures taken to make roads pothole free.

28. For Govt. of NCT of Delhi, Shri A.K. Singh, Principal Secretary, Environment and Forest Department, is present and made the following consolidated compliance through a power-point presentation on the various directions dated 17.4.2023 of the Commission to the Govt. of NCT of Delhi. He states that, during January 2023, 66,015 samples were tested, out of which 65,698 samples were found satisfactory and 317 were unsatisfactory. However, after rechecking of water samples, all unsatisfactory samples were found fit. The details of area/location-wise status and re-checking of unfit samples were also given in a separate annexure. Cleaning sewer lines/septic tanks are done through specialized agencies u/s 23 of Contract Labour (Regulation & Abolition) Act, 1970. The concerned Department of the Government is responsible for the safety of departmental and contract workers. Delhi Jal Board had surveyed all its safety equipment through Director (Safety & Disaster Management), DJB. Out of 23,378 safety equipment, 96 were found unfit.

29. Similarly, a fitness survey of the MCD, NDMC and DCB safety equipment was conducted, and all the equipment was found fit for use. The MCD requires 13,288 more protective gear/safety equipment for 2023-2024, which will be procured by 15.8.2023. With respect to mechanized cleaning of sewer lines/septic tanks by DJB, after extensive study of the system of the Hyderabad model, DJB designed a prototype which is technologically advanced and equipped with all functions that may be required at the site for sewer maintenance and to meet the specific requirement of manoeuvrability in the overcrowded narrow streets and lanes of Delhi. It has been tested successfully and 189 such machines are in operation. A comparison between Hyderabad and Delhi Jal Board Models was also explained. At present, the coverage of the sewerage network in Delhi is about 82%. An action plan has also been prepared for laying sewerage infrastructure in the balance un-severed areas of Delhi comprising 960 numbers out of 1,799 numbers of unauthorized colonies. NDMC has already adopted the Hyderabad Model of mechanized cleaning of sewer lines and septic tanks, and no manual cleaning work is being executed in the entire NDMC area. The Delhi Cantonment Board has not adopted the Hyderabad Model. However, it is exploring further possibilities of mechanization for the sewer lines.

30. Stating about the cleaning of MSW from railway lines, they informed that a pilot study from Azadpur to Narela stretch was carried out jointly by Railway and MCD officers for improving sanitation around Railway tracks and stations and to re-assess the MSW lying along Railway tracks. The MSW lying is 3,550 MT against the earlier assessment of 10,000 MT. Out of that, 1,600 MT of MSW has been lifted to date, and the remaining 1,950 MT will be cleared by 15.7.2023. A joint inspection with Railway officials for the balance Railway line in Delhi is in progress to assess the existing garbage lying on the railway track, and it has been assessed that

Template for Information in Compliance to the direction of NHRC Hearing dated 04.07.2023

Sr. No.	NHRC Directions	Concerned Departments	Response
1	a. **A matrix chart containing a District wise list of Corporations and Urban Local Bodies (in rows) and showing different kinds of machinery and safety equipments (in columns). The numbers of the available machinery and safety equipments should be mentioned therein against each of these Corporations and Urban Local Bodies (sample list of Punjab is attached as Annexure "A").**	Urban Development/Social Welfare/Infrastructure and Industrial Development /Housing and Urban Development.	Not Related
2	b. **A separate matrix chart should also show, in respect of each of the Corporations and Urban Local Bodies, the following information: what types and numbers of more machinery and safety equipments have to be purchased to meet their needs; whether mechanical cleaning of sewer line / septic tanks is being done; whether the Hyderabad model of mechanical cleaning for sewer line / septic tanks is being followed; etc.**	Urban Development/Social Welfare/ Infrastructure and Industrial Development / Housing and Urban Development.	Not Related

Sr. No.	NHRC Directions	Concerned Departments	Response
3	c. Para-wise reply on each recommendation made in the Commission's Advisory dated 24.09.2021 relating to Human Rights of Workers engaged in hazardous cleaning of sewer line / septic tanks.	Urban Development/ Social Welfare	Not Related
4	d. A road map to purchase all the required machinery and safety equipments. This road map should also encompass complete mechanical cleaning of all sewer lines / septic tanks; installation of alert lights in all sewer lines / septic tanks to detect presence of poisonous gases in them; plan to implement each of the recommendations made in the Commission's Advisory dated 24.09.2021; requisite budgetary provisions; and timeframe for procurement / implementation.	Urban Development/ Social Welfare	Not Related
5	e. List of Welfare Schemes and Rehabilitation Schemes of the State Government for NoK of victims of hazardous cleaning of sewer line / septic tanks (other than the compensation of Rs.10 lakhs as per	Urban Development/ Social Welfare	Not Related

Sr. No.	NHRC Directions	Concerned Departments	Response
	directions of Hon'ble Supreme Court).		
6	f. Comprehensive report on the steps taken and proposed to be taken on different schemes of the Government of India to eliminate hazardous cleaning and adoption of mechanical cleaning of sewer line/ septic tanks, including Smart Cities Mission and "Safai Mitra Suraksha Shehar" protocol (as issued by the Ministry of Housing and Urban Affairs, Government of India, vide letter dated 02.08.2022).	Urban Development/Social Welfare/Infrastructure and Industrial Development /Housing and Urban Development.	Not Related
7	a. The last social welfare meeting was held in 2019. The reasons for not having such meetings after that. Date for next meeting be submitted.	Social Welfare Department	Not Related
8	b. What time frame the state will meet the gap of TPD of solid waste.	Urban Development	Not Related
9	c. Steps taken to promote sowing more basmati rice by the farmers.	Agriculture Department	Not Related
10	d. Whether the state has reserved CRM machines for low-income farmers, who cannot afford it. If not done, adequate number be reserved and details of such	Agriculture Department	Not Related

Sr. No.	NHRC Directions	Concerned Departments	Response
	machines reserved be submitted to the Commission.		
11	**e. Figures and details where plants and trees were planted and whether any third party is doing any survey about its survival. If so, reports thereof.**	Forest Department	Not Related
12	**f. The latest figures where measures taken to make roads pothole free.**	PWD	1. Before the monsoon amount of Rs. 86.83 Cr. has been released to keep the roads traffic worthy. 2. In wake of monsoon damages a detailed action plan has been asked from all Districts. Based on the requirement the funds would be released as per available financial resources to make roads pothole free just after the monsoon.

प्रदेश के समस्त श्रेणी के मार्गों को गड्ढामुक्त करने हेतु लक्ष्य एवं प्रगति का विवरण (वि.व-23-24)

दिनांक 15.08.2023 तक

क्रम सं0	विभाग का नाम	गड्ढामुक्ति हेतु लक्ष्य			टिप्पणी
		पैच मरम्मत हेतु	नवीनीकरण / रेस्टोरेशन हेतु	कुल योग (3+4)	
1	2	3	4	5	6
1	लोक निर्माण विभाग	44500.00	17408.00	**61908.00**	1– सुगम यातायात बनाये रखने एवं आवश्यकतानुसार अनुरक्षण कराये जाने हेतु मानसून से पूर्व रू0 86.83 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। 2– वर्षा के कारण क्षतिग्रस्त मार्गों की विस्तृत कार्ययोजना सभी जनपदों से मांगी गयी है। उपलब्ध संसाधनों से क्षतिग्रस्त मार्गों पर अनुरक्षण हेतु धनराशि शीघ्र ही निर्गत की जायेगी।
2	राष्ट्रीय मार्ग	560.06	48.30	**608.36**	
3	**NHAI (West UP)**	126.90	142.00	**268.90**	
4	NHAI (East UP)			**0.00**	
5	मण्डी			**0.00**	
6	पंचायती राज	366.11	832.14	**1198.25**	
7	सिंचाई विभाग				क्षेत्रीय संगठनों से कार्य योजना का प्रस्ताव प्राप्त किया जा रहा है 15 सितंबर तक कार्य योजना का अनुमोदन कर लिया जाएगा!
8	ग्राम्य विकास **(UPRRDA)**		4371.64	**4371.64**	योजनान्तर्गत निर्मित मार्गों के 05 वर्षीय अनुरक्षण के उपरान्त मार्गों का नवीनीकरण कार्य कराये जाने के पश्चात 4371.64 किमी लम्बाई का अनुरक्षण कराया जा रहा है।
9	नगर विकास	1974.73	1278.37	**3253.10**	
10	गन्ना विभाग	249.00	2286.00	**2535.00**	चीनी मिल परीक्षेत्र से सम्बन्धित जनपदों में लोक निर्माण विभाग एवं गन्ना विभाग के संयुक्त निरीक्षण के पश्चात मार्गों की कार्ययोजना तैयार कर उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये है।
11	आवास एवं शहरी नियोजन			**0.00**	
12	अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास			**0.00**	
	योग	**47776.80**	**26366.45**	**74143.25**	

प्रदेश के समस्त श्रेणी के मार्गों को गड्ढामुक्त करने हेतु लक्ष्य एवं प्रगति का विवरण (वि.व-22-23)

दिनांक 31.03.2023 तक

Length in Kms

क्रम सं0	विभाग का नाम	रोड डायरेक्ट्री के आधार पर		गड्ढामुक्ति हेतु लक्ष्य			गड्ढामुक्ति कार्य की प्रगति			प्रगति गड्ढामुक्त कार्यो की प्रतिशत (Col 8/5)	प्रगति (नवीनीकरण एवं रेस्टोरेशन) प्रतिशत (Col 9/6)	आख्या अपडेट की अंतिम तिथि
		मार्गो की कुल संख्या	मार्गो की कुल लम्बाई	केवल गड्ढामुक्ति हेतु	नवीनीकरण/रेस्टोरेशन हेतु	कुल योग (5+6)	केवल गड्ढामुक्ति हेतु	नवीनीकरण/रेस्टोरेशन हेतु	कुल योग (8+9)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	लोक निर्माण विभाग	114475	276042.00	60497.04	23603.89	84100.93	60497.04	23295.81	83792.85	100%	99%	31-Mar
2	राष्ट्रीय मार्ग	48	11424.00	897.79	129.00	1026.79	879.03	129.00	1008.03	98%	100%	31-Dec
3	NHAI (West UP)	50		264.40	20.00	284.40	263.55	19.50	283.05	100%	98%	31-Dec
4	NHAI (East UP)	32		97.30	133.00	230.30	97.04	133.00	230.04	100%	100%	31-Dec
5	मण्डी	12619	20492.34	450.00	598.93	1048.93	450.00	598.93	1048.93	100%	100%	31-Mar
6	पंचायती राज	26770	18034.93	366.11	832.14	1198.25	366.11	763.94	1130.05	100%	92%	31-Dec
7	सिंचाई विभाग	898	5223.00	339.12	1612.51	1951.62	339.12	789.88	1129.00	100%	49%	31-Dec
8	ग्राम्य विकास(UPRRDA)	2892	15094.56	2182.65	1093.17	3275.82	2155.49	1031.74	3187.23	99%	94%	31-Dec
9	नगर विकास	69195	43042.19	1974.00	1278.37	3252.37	1974.00	1258.76	3232.76	100%	98%	31-Mar
10	गन्ना विभाग	7605	8048.00	249.00	2286.00	2535.00	0.00	561.64	561.64	0%	25%	31-Mar
11	आवास एव शहरी नियोजन	373	888.88	56.40	91.31	147.71	56.40	90.40	146.80	100%	99%	31-Mar
12	अवस्थापना एव औद्योगिक विकास	3882	2734.74	89.62	183.91	273.53	89.57	171.42	260.99	100%	93%	31-Dec
	योग	238839.00	401024.64	67463.42	31862.23	99325.65	67167.35	28844.02	96011.37	100%	91%	